

प्रेषक,

डा० राकेश कुमार,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्राचार्य,  
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान,  
पौड़ी गढ़वाल।

चिकित्सा अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक ०१ दिसम्बर, 2008

विषय: वीर चन्द्र गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर के प्रथम चरण के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-मे०का०/आर०एन०एन०/2008/505 दिनांक 20 अगस्त, 2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रीनगर मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-1614/XXVIII(1)/2007-19/2006 दिनांक 29 अक्टूबर, 2007 द्वारा स्वीकृत कार्य को पूर्ण करने हेतु तदस्थान में स्वीकृत लागत के सापेक्ष व्यय हेतु रुपये 500.00 लाख (रुपये पाँच करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. व्यय वित्त समिति की दिनांक 26.06.2007 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त में उल्लिखित शर्त के अनुसार निर्माण कार्य के लिए दिए गये दिशा-निर्देशों तथा पूर्व निर्गत शासनादेशों की बातों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि व्यय वित्त समिति द्वारा स्वीकृत कार्य पर ही तथा स्वीकृत लागत की सीमा तक ही व्यय की जायेगी।
2. कार्य कराते समय स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेंसी का होगा। किसी भी परिस्थिति में निर्माण एजेंसी द्वारा प्ररुणगत कार्यों की subcontracting नहीं की जायेगी।
3. उक्त धनराशि में से 97.5 प्रतिशत ही आहरित कर परियोजना प्रबन्धक उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम, लि० इकाई-2 श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल को उपलब्ध करायी जायेगी। शेष 2.5 प्रतिशत धनराशि को Defect Liability के रूप में रखा जायेगा। यह 2.5 प्रतिशत धनराशि लो०नि०विभाग द्वारा निर्मित भवनों की जाँच कर Satisfactory Certificate दिये जाने के उपरान्त निर्गत की जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दश में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा। निर्माण एजेंसी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि कार्य स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जायेगा तथा किसी भी दश में लागत पुनरीक्षित नहीं की जायेगी।
4. शासन को यह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि उक्त कार्य की स्वीकृति पूर्व में किसी भी योजना में नहीं हुई है।
5. उक्त कार्य हेतु थर्ड पार्टी से गुणवत्ता/प्रगति की जाँच सी०बी०आर०आई०रूडकी या अन्य किसी प्रतिष्ठित संस्था से करायी जाय। इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सैटेज चार्ज से वहन किया जायेगा तथा इस हेतु अलग से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी। कार्य कराने से पूर्व विरतृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दश में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
6. उ०प्र० राजकीय निर्माण लि० द्वारा आर्किटेक्ट द्वारा भवन को डिजाइन कराया जायेगा। आर्किटेक्ट के सम्बन्ध में निर्माण एजेंसी द्वारा प्राचार्य के माध्यम से शासन से पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित बाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पृस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के सक्षम स्तर द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।
9. कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत नाम्स हैं, स्वीकृत नाम्स से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
10. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाये।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि उल्लिखित कार्य हेतु ही व्यय की जाय, एवं अन्यत्र/अन्य कार्य हेतु व्यय कदापि न किया जाय। निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाए, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लायी जाए।
12. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करे।
13. स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या दशा में माह 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मित किया गया है।
14. कार्य कराने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली-भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाये।
15. आगणन में कोर्टज आदि की दूरिया तथा दुलान की दरों को विस्तृत आगणन गठित करते समय अक्षीक्षण अभियन्ता स्थल आवश्यकतानुसार सभी मदों को पुनः परीक्षण कर प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेगा कि दुलान आदि तथा एक मुश्त प्राविधानों को शत प्रतिशत जाँच के उपरान्त भुगतान किया गया है तथा उसकी पुष्टि हेतु शासन को भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
16. योजना के कार्यों को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए, ताकि लागत पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पड़े।
17. धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार अथवा मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाय।
18. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-12 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान -105-एलोपैथिक-03-श्रीनगर में मेडिकल कालेज की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के नामे डाला जाय।
19. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-234(P)/वित्त अनुभाग-3/2007 दिनांक 05 दिसम्बर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० राकेश कुमार)  
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री।
2. महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
4. सहायक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, पौड़ी।

7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. कोषाधिकारी, पौड़ी।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी।
10. मुख्य चिकित्साधीक्षक, श्रीनगर बेस चिकित्सालय, श्रीनगर।
11. परियोजन प्रबन्धक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम, लि० इकाई-2 श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।
12. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
13. वित्त अनुभाग-3/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(मायावती ढकरियाल)  
उप सचिव।